भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

उच्चतर शिक्षा विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1967

उत्तर देने की तारीख-05/08/2026

कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) उत्कृष्टता केंद्र

1967 **श्री मिलिंद मुरली देवरा:**

क्या ***शिक्षा*** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मेजबान संस्थान, प्रमुख कार्यक्षेत्र, स्थान तथा संस्वीकृत परिव्यय के ब्यौरे सहित वर्ष 2021-22 से अब तक स्थापित अथवा स्वीकृत किए गए कृत्रिम बुद्धिमत्ता उत्कृष्टता केंद्रों (एआईसीओई) का ब्यौरा क्या है;

(ख) प्रत्येक उत्कृष्टता केंद्र को संस्वीकृति की तिथि से अब तक आवंटित, निर्गत की गई तथा उनके द्वारा उपयोग की गई निधियों का वर्ष-वार और राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) प्रत्येक उत्कृष्टता केंद्र द्वारा किए गए अनुसंधान के वर्ष-वार परिणामों, दायर किए गए पेटेंटों, विकसित कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) मॉडलों और संवर्धित स्टार्टअप्स का ब्यौरा क्या है;

(घ) बजट 2025-26 में ₹500 करोड़ के परिव्यय के साथ घोषित शिक्षा क्षेत्र के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता उत्कृष्टता केंद्र (एआई उत्कृष्टता केंद्र) की वर्तमान स्थिति क्या है, जिसमें नोडल संस्थान के चयन और उसके कार्यान्वयन की समय-सीमा का ब्यौरा शामिल है; और

(ङ) क्या कृषि, स्वास्थ्य सेवा और संधारणीय शहरों के लिए स्थापित कृत्रिम बुद्धिमत्ता उत्कृष्टता केंद्रों द्वारा निधियों के उपयोग का मूल्यांकन किया गया है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(डॉ. सुकान्त मजूमदार)

(क) से (घ) भारत सरकार ने केंद्रीय बजट 2023-24 में की गई घोषणा के बाद कृषि, सतत शहरों और स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्रों में" मेक एआई इन इंडिया एंड मेक एआई वर्क फॉर इंडिया" के दृष्टिकोण के तहत कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) में तीन उत्कृष्टता केंद्र (सीओई) स्थापित किए हैं। इन एआई-सीओई का नेतृत्व क्रमशः आईआईटी रोपड़, आईआईटी कानपुर और आईआईएससी बैंगलोर कर रहे हैं। इन तीन एआई-सीओई के लिए कुल बजट परिव्यय 990 करोड़ रुपये है।

इस दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने के लिए, केंद्रीय बजट 2025-26 में, शिक्षा के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) में उत्कृष्टता केंद्र (सीओई) की घोषणा की गई थी, जिसकी कुल परिव्यय राशि 500 करोड़ रुपये थी, जिसे आईआईटी मद्रास में स्थापित किया गया है।

(ख) एआई-सीओई पहल के तहत जारी की गई वित्तीय सहायता निम्नानुसार है। वित्त वर्ष 2023-24 और वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान, संस्थानों के प्रतिस्पर्धी चयन के लिए प्रायोगिक चरण में, संस्थान संघों को 27.00 करोड़ रुपये जारी किए गए थे। अब तक, वित्त वर्ष 2025-26 और 2026-27 के दौरान, आईआईटी कानपुर को 74.39 करोड़ रुपये, आईआईटी रोपड़ को 62.64 करोड़ रुपये, आईआईएससी बेंगलुरु को 69.07 करोड़ रुपये और आईआईटी मद्रास को 43.00 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं।

(ग) चार एआई-सीओई ने शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, कृषि और सतत शहरों के क्षेत्रों में चुनौतियों का समाधान करने के लिए शैक्षणिक संस्थानों, उद्योग और सरकारी संगठनों के एक नेटवर्क के साथ साझेदारी में अनुसंधान प्रकाशित किया है और एआई-मॉडल विकसित किए हैं।

शिक्षा के लिए एआई-सीओई ने ऑटोमेटिक स्पीच रिकग्निशन (एएसआर), ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन (ओसीआर), मशीन ट्रांसलेशन (एमटी), और टेक्स्ट-टू-स्पीच (टीटीएस) के लिए मशीन लर्निंग मॉडल विकसित किए हैं जो भारतीय भाषाओं का समर्थन करते हैं। कृषि के लिए एआई-सीओई ने फसल, कीट और बीमारी की पहचान के लिए मॉडल विकसित किए हैं। इसी तरह, सतत शहरों के लिए एआई सीओई ने एयर प्ल्युशन एट्रिब्यूशन और शहरी बाढ़ की भविष्यवाणी के लिए मॉडल विकसित किए हैं।

(ड.) एआई-सीओई की प्रगति की निगरानी उद्योग नेतृत्वकर्ताओं और वरिष्ठ प्रशासकों से मिलाकर बनी शीर्ष समिति द्वारा की गई समीक्षा सहित बहुस्तरीय शासन और वित्तीय निगरानी तंत्र के माध्यम से की जाती है। निजी परियोजनाओं की प्रगति की निगरानी करने के लिए एआई-सीओई द्वारा एक स्वतंत्र परियोजना निगरानी और समीक्षा समिति (पीएमआरसी) का गठन किया गया है। इसके अलावा, केंद्रीय परियोजना प्रबंधन इकाई (सीपीएमयू) ने बाह्य क्षेत्र विशेषज्ञों द्वारा समय-समय पर समीक्षा आयोजित की है। समीक्षाओं ने अनुमोदित प्रदेयों और वित्तीय उपयोगिता की तुलना में प्रौद्योगिकी विकास में प्रगति का आकलन किया है।

*****